आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1993)
(13-18)

न्यायमूर्ति के. कन्नन के समक्ष

श्रीमती.कृष्णा ,श्री राम कुमार की पत्नी, याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती. कांता आनंद सरूप की विधवा और अन्य ,उत्तरदाता

2012 की सी.आर. संख्या 3029

-4 सितंबर 2013

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 39, नियम 1 और 2 - अस्थायी निषेधाज्ञा - यथास्थिति - यथास्थिति आदेश पारित करके एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी - माना गया कि किसी न्यायाधीश के लिए यथास्थिति क्या है, यह बताए बिना यथास्थिति का आदेश पारित करना अनुचित है - यथास्थिति संपत्ति को संरक्षित करने का एक तरीका है, यदि प्रथम दृष्टया निषेधाज्ञा की मांग करने वाला मामला स्थापित हो जाता है - हालांकि, पुलिस सुरक्षा का आदेश देते हुए, न्यायालय ने दर्ज किया कि वादी-उप पट्टेदार के पास पट्टेदार के अधीन वाद भूमि का कब्जा था और इसलिए, कब्जे की रक्षा करना आवश्यक था - यद्यपि तर्क असंतोषजनक था लेकिन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा था - न्यायालय के अंतिम निर्णय को कायम रखा जाना था।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि किसी न्यायाधीश के लिए यथास्थिति का आदेश पारित करना बेहद अनुचित है, बिना यह बताए कि यथास्थिति क्या है। निषेधाज्ञा की निवारक राहत में, अनिवार्य राहत के विपरीत, अदालतें 4 कारकों द्वारा निर्देशित होती हैं: (I) पार्टी का प्रथम दृष्टया मामला, जो निषेधाज्ञा चाहता है; (ii) उसके पक्ष में सुविधा का संतुलन; (ii) यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति और कठिनाई; और (iv) यथास्थिति बनाए रखना। यथास्थिति संपत्ति को संरक्षित

करने का एक तरीका है, यदि याचिकाकर्ता का प्रथम दृष्टया निषेधाज्ञा की मांग करने वाला मामला स्थापित हो जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थिति, जैसा कि अदालत ने कहा और पाया, संरक्षित रहे। यह कभी नहीं समझा जाना चाहिए कि ऐसा आदेश तब पारित किया जा सकता है जब न्यायालय यह तय करने में दुविधा में हो कि वादी का कब्ज़ा है या प्रतिवादी का कब्ज़ा है। यह कभी भी अनिर्णय का आदेश नहीं होगा, बल्कि न्यायालय द्वारा सचेत रूप से दिमाग लगाने पर दिया गया आदेश होगा कि संपत्ति की स्थिति क्या है और इसे कैसे संरक्षित किया जाएगा। एक पंक्ति का आदेश जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, आदेश 39 नियम 1 और 2 सी.पी.सी. के तहत शासनादेश के विरुद्ध है।

(पैरा 3)

आगे यह अभिनिर्णीत किया गया कि जिस प्रावधान के लिए एक आदेश की आवश्यकता होती है जिसे न्यायालय आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत पारित कर सकता है, आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत कारण बताना आवश्यक है। यदि न्यायालय केवल नोटिस देने का आदेश दे रहा है, तो कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि न्यायालय एक पक्षीय निषेधाज्ञा देता है, भले ही वह नियम 3 के परंतुक के आधार पर यथास्थिति का आदेश हो, तो न्यायालय इसके कारणों को दर्ज करेगा कि यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। किसी पीठासीन अधिकारी के लिए इस तरह का आदेश पारित करना मामले के तथ्यों से तुरंत बाहर निकलने के रूप में देखा जाता है, जहां उसे कब्जे के पहलू के बारे में किसी न किसी तरह से पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती है। यथास्थिति आदेश पार्टियों के लिए भ्रम पैदा करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि न्यायालय एक या दूसरे पक्ष के हाथों में कब्जे के संबंध में अपने निष्कर्ष को उसी क्रम में सामने नहीं लाता। यदि कभी ऐसा हुआ कि न्यायालय निषेधाज्ञा मांगने वाले व्यक्ति के हाथ में कब्जे का कोई निश्चित मामला खोजने में असमर्थ है, तो यह केवल यह माना जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता है और

अंतरिम राहत का पक्ष नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित करने का कोई रास्ता नहीं है।। यदि कब्जे के लिए हाथापाई हो रही है और न्यायालय की राय है कि कानून और व्यवस्था संरक्षित है, तो वह एक रिसीवर नियुक्त करने के लिए भी सक्षम है, हालांकि याचिका केवल निषेधाज्ञा के लिए है। यह केवल आदेश की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए है जो संभव है लेकिन जरूरी नहीं कि इस मामले में केवल वही आदेश पारित किया जा सकता था।

(पैरा 4)

श्री अरुण बंसल याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

श्री मृगांक शर्मा प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता

न्यायमूर्ति के. कन्नन,

(1) पुनरीक्षण पुलिस सुरक्षा देने के आदेश के विरुद्ध है। न्यायालय ने कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया है जो उचित नहीं हैं। मैं गलतियों को स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

(2) निषेधाज्ञा के वाद में वादी ने निषेधाज्ञा से अंतरिम राहत भी मांगी है। वादी का तर्क था कि वह मघा राम के अधीन पट्टेदार था। ऐसा प्रतीत होता है कि मघा राम ने स्वयं हरिओम और ओमपति से संपत्ति पट्टे पर ली थी। मुकदमे में प्रतिवादी कृष्णा है, जिसने हरिओम और ओमपति से खरीदार के रूप में संपत्ति का दावा किया था। प्रतिवादी द्वारा पहले एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि मघा राम के पक्ष में पट्टा सही और वैध नहीं था और दावा किया था कि संपत्ति उसके कब्जे में थी। मामला इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसकी याचिका स्वीकार्य नहीं है और मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मघा राम के पट्टेदार आनंद सरूप ने निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान मुकदमा यह कहते हुए दायर किया है कि

प्रतिवादी ने पहले उसके खिलाफ कब्जे का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया था, और उक्त मुकदमे की बर्खास्तगी पर उसके कब्जे के दावे की पुष्टि के रूप में भरोसा किया जाएगा। जब मुकदमा दायर किया गया, तो ऐसा प्रतीत होता है, अपील अभी भी लंबित थी। ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए पक्षों को वाद भूमि पर कब्जे और फसलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, दिनांक 31.03.2010 को पारित किया था। वादी ने 31.03.2010 को जारी आदेश का हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि यथास्थिति आदेश जारी होने के बावजूद, प्रतिवादी उसके कब्जे में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। न्यायालय ने पुलिस सुरक्षा की अनुमति देते हुए और आदेश का औचित्य निर्धारित करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। 25.04.2012 को जारी यह आदेश ही मेरे समक्ष चुनौती है।

(3) मुझे यह अवश्य मानना चाहिए कि किसी न्यायाधीश के लिए यथास्थिति का आदेश पारित करना, यह बताए बिना कि यथास्थिति क्या है, अत्यंत अनुचित है। निषेधाज्ञा की निवारक राहत में, अनिवार्य राहत के विपरीत, अदालतें 4 कारकों द्वारा निर्देशित होती हैं: (i) पार्टी का प्रथम दृष्टया मामला, जो निषेधाज्ञा चाहता है; (ii) उसके पक्ष में सुविधा का संतुलन; (iii) यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति और कठिनाई; और (iv) यथास्थिति बनाए रखना। यथास्थिति संपत्ति को संरक्षित करने का एक तरीका है, यदि याचिकाकर्ता का प्रथम दृष्टया निषेधाज्ञा की मांग करने वाला मामला स्थापित हो जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थिति, जैसा कि अदालत ने कहा और पाया, संरक्षित रहे। यह कभी नहीं समझा जाना चाहिए कि ऐसा आदेश तब पारित किया जा सकता है जब न्यायालय यह तय करने में दुविधा में हो कि वादी का कब्ज़ा है या प्रतिवादी का कब्ज़ा है। यह कभी भी अनिर्णय का आदेश नहीं होगा, बल्कि न्यायालय द्वारा सचेत रूप से दिमाग लगाने पर दिया गया आदेश होगा कि संपत्ति की स्थिति क्या है और इसे कैसे संरक्षित किया जाएगा। 31.03.2010 को पारित एक पंक्ति का आदेश जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था, आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत शासनादेश के

कृष्णा बनाम कांता और अन्य
(न्यायमूर्ति के. कन्नन)

खिलाफ है और किशोर कुमार खेतान और अन्य बनाम प्रवीण कुमार सिंह [1]में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है , जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमेबाजी के प्रारंभिक चरण में यथास्थिति का संकेत दिए बिना आदेश पारित करने के लिए एक न्यायालय की अनुचितता के बारे में टिप्पणी की। अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश की प्रकृति के बारे में बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“इस स्तर पर यह नोटिस करना आवश्यक है कि इस प्रकृति के एक मूल मुकदमे में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के लिए पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करना उचित नहीं था, बिना यह बताए कि यथास्थिति क्या थी। यदि वह इस बात से संतुष्ट था कि उसके सामने अपीलकर्ता ने एक अंतरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया था और सुविधा के संतुलन ने इस तरह के निषेधाज्ञा के अनुदान को उचित ठहराया था, तो उसके लिए निषेधाज्ञा का ऐसा आदेश पारित करना था। लेकिन केवल यथास्थिति बनाए रखने के लिए पक्षों को यह बताए बिना कि यथास्थिति क्या है, एक ऐसा आदेश नहीं है जिसे मुकदमेबाजी के प्रारंभिक चरण में पारित किया जाना चाहिए, खासकर जब एक अदालत को निषेधाज्ञा का एक पक्षीय आदेश देने का कोई कारण नहीं मिला हो और अपीलीय न्यायालय केवल सीमित प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना चाहिए था या नहीं, क्योंकि अपील केवल निषेधाज्ञा के एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश और मुख्य आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ थी। निषेधाज्ञा के लिए लंबित मुकदमा, अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित था। इसलिए, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को मामले की परिस्थितियों में पारित आदेश की तरह गोलमोल आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। “

(4) आदेश 39 नियम 1 और 2 सी.पी.सी. के तहत पारित आदेश में आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत कारण बताना आवश्यक है। यदि न्यायालय केवल नोटिस देने का आदेश दे रहा है, तो कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि न्यायालय एक पक्षीय निषेधाज्ञा देता

---

[1] (2006) 3 एस.सी.सी. 312

है, भले ही वह नियम 3 के परंतुक के आधार पर यथास्थिति का आदेश हो, तो न्यायालय इसके कारणों को दर्ज करेगा इसकी राय है कि यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। मैं उस आदेश को तब समझ पाऊंगा जब न्यायालय ने यथास्थिति प्रदान करने वाला आदेश पारित किया था, वह अपने दिमाग का उपयोग किए बिना और यह बताए बिना कि यथास्थिति क्या थी, एक आदेश पारित कर रहा था। किसी पीठासीन अधिकारी के लिए इस तरह का आदेश पारित करना मामले के तथ्यों से तुरंत बाहर निकलने के रूप में देखा जाता है, जहां उसे कब्जे के पहलू के बारे में एक या दूसरे तरीके से पकड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती है। यथास्थिति आदेश पार्टियों के लिए भ्रम पैदा करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि न्यायालय एक या दूसरे पक्ष के हाथों में कब्जे के संबंध में अपने निष्कर्ष को उसी क्रम में सामने नहीं लाता। यदि कभी ऐसा हुआ कि न्यायालय निषेधाज्ञा मांगने वाले व्यक्ति के हाथ में कब्जे का कोई निश्चित मामला खोजने में असमर्थ है, तो यह केवल यह माना जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता है और अंतरिम राहत का पक्ष नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित करने का कोई रास्ता नहीं है।। यदि कब्जे के लिए हाथापाई हो रही है और न्यायालय की राय है कि कानून और व्यवस्था संरक्षित है, तो वह एक रिसीवर नियुक्त करने के लिए भी सक्षम है, हालांकि याचिका केवल निषेधाज्ञा के लिए है। यह केवल आदेश की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए है जो संभव है लेकिन जरूरी नहीं कि इस मामले में केवल वही आदेश पारित किया जा सकता था।

(5) यह यथास्थिति आदेश है जिसका उपयोग वादी द्वारा बाद के चरण में पुलिस सुरक्षा की मांग के लिए किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में, मैं आदेश को रद्द कर देता और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज देता, लेकिन पुलिस सुरक्षा का आदेश देने वाले आवेदन में, अदालत ने अपने आदेश को सही ठहराने और वादी के हाथों में कब्जे का मामला खोजने की कोशिश की है, जो कार्य इसे उस समय शुरू करना चाहिए था जब इसने मूल रूप से 31.03.2010 को आदेश

पारित किया था। तथ्यों के वर्णन में भी, न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ कुछ मुकदमे दायर किए गए हैं। संदर्भ प्रतिवादी द्वारा मघा राम के पक्ष में पट्टे के संबंध में एक मुकदमे का होना चाहिए था, न कि वर्तमान वादी के खिलाफ। वर्तमान वादी मघा राम के अधीन उप पट्टेदार के रूप में दावा करता है। वादी का अपना मामला और निषेधाज्ञा के लिए उसका दावा केवल इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी अपना कब्ज़ा स्थापित करने में विफल रहने और मघा राम के पक्ष में पट्टे पर हमला करने के अपने प्रयास में विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय तक मुकदमे के पहले दौर में हार गया था। पट्टे को उसके पक्ष में चुनौती देने वाले वर्तमान वादी-अपीलकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए उसका अपना अगला मुकदमा भी खारिज कर दिया गया प्रतीत होता है और यहां तक कि अपील भी खारिज कर दी गई थी। विभिन्न समयों पर प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज करना स्वयं ऐसे कारक हैं जो साबित करते हैं कि पट्टेदार माघ राम और उप-पट्टेदार- वर्तमान वादी ऐसे व्यक्ति हैं, जो कब्जे में हैं और इसलिए, उस कब्जे की रक्षा करना आवश्यक था। यद्यपि तर्क, जैसा कि अदालत के आदेश में पाया गया है, असंतोषजनक है, मैंने सभी तथ्यों पर समग्र विचार करने पर देखा है कि न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है, हालांकि खराब तर्क के माध्यम से। मैं अभी भी अंतिम निर्णय पर कायम हूं और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है ।

एस.गुप्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh